

2



दबंग किसान के बेटे ने कार से टक्कर मारी

3



प्राधिकरण में अब सभी मंत्री होंगे सदस्य

5



आम आदमी पार्टी की नई नायक बनी आतिशी मार्लेना

RNI-MPBIL/2011/39805

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

# जगत प्रवाह

वर्ष : 15 अंक : 20

प्रति सोमवार, 23 सितंबर 2024

मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

शिखर की ओर साय सरकार

## विष्णुदेव सरकार ने जीता युवाओं का भरोसा, आदिवासी बेरोजगार युवाओं के सपनों को लगाये पंख

कवर स्टोरी

-विजया पाठक  
एडिटर

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार निरंतर जन कल्याण की दिशा में कार्य कर रही है। साय सरकार ने चरणबद्ध ढंग से महिलाओं, बच्चों, बेटीयों, युवाओं, बुजुर्गों और कामगारों के लिये लाभकारी योजनाओं का निर्माण कर उन्हें संबल देने का कार्य किया है। इसी क्रम में साय सरकार ने युवाओं को

कौशल विकास के क्षेत्र में मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से नया कदम बढ़ा रही है। अब राज्य में युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर उन्हें विशेष रोजगार परक प्रशिक्षण देने की योजना पर कार्य आरंभ हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासी समुदायों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। विभिन्न पहलों के माध्यम से, सड़क, स्कूल और स्वास्थ्य सेवा जैसी बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है। ये प्रयास आदिवासी युवाओं के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रख रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य ने कई ऐसी योजनाएं शुरू की हैं, जो जमीनी स्तर पर लोगों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही हैं। ऐसी ही एक पहल है नियत नेलनार योजना, जो माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में आवास, अस्पताल, पानी, बिजली, पुल और स्कूल जैसे आवश्यक संसाधनों के विकास पर केंद्रित है। (शेष पेज 7 पर)



सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी करने का अवसर

सरकार नई दिल्ली में जनजातीय युवा छात्रावास में सीटें 50 से बढ़ाकर 185 करके जनजातीय युवाओं के लिए अवसर बढ़ा रही है। इससे अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अधिक अभ्यर्थियों को राजधानी में रहते हुए सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी करने का अवसर मिलेगा। बुनियादी ढांचे में सुधार एक और प्रमुख फोकस क्षेत्र है। सरकार को दूरदराज के आदिवासी इलाकों से अयोध्या धाम तक सीधी कनेक्टिविटी बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है। सड़क विकास परियोजनाएं इन क्षेत्रों के निवासियों के लिए यात्रा को आसान बना रही हैं।

नक्सल हिंसा से पीड़ित बस्तर के लोगों से मिले गृह मंत्री अमित शाह, दोहराया 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प



केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। उन्होंने माओवादियों से हिंसा छोड़ने, हथियार डालने और आत्मसमर्पण करने की भी अपील की। नक्सली हिंसा के 55 पीड़ितों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कहा, "हम इस देश से नक्सलवाद और नक्सलवाद के विचार को उखाड़ फेंके और शांति स्थापित करेंगे। छत्तीसगढ़ बस्तर में नक्सल प्रभावित और पीड़ित लोगों से मिलने के बाद अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार बस्तर के 4 जिलों को छोड़कर पूरे देश में नक्सलवाद को खत्म करने में सफल रही है। उन्होंने कहा कि इस देश से नक्सलवाद को अंतिम विदाई देने के लिए 31.03.2026 की तारीख तय की गई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उससे पहले नक्सलवाद खत्म हो जाएगा।

कर्ज के दलदल में धंसी मोहन यादव सरकार

पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार को घेरा

-विजया पाठक

मध्यप्रदेश की 'मोहन सरकार' पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। विरासत में मिले इस कर्ज से मध्यप्रदेश की 'मोहन सरकार' पर कर्ज का बंधन बढ़ा है। सरकार 4.23 लाख करोड़ के कर्ज में डूबी है। पिछले 15 महीने में ही सरकार 17 बार कर्ज ले चुकी है। 02 साल में 98 हजार करोड़ का कर्ज एमपी सरकार ने केंद्र से लिया है। अब फिर सरकार कर्ज लेने की तैयारी में है। बता दें अगस्त में एमपी सरकार 10 हजार करोड़ कर्ज ले चुकी है। बताया जा रहा है कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश के विकास को लेकर लगातार कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन विकास का यह कार्य वे उधार लिये हुए पैसों से कर रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि अखिर मध्यप्रदेश के सिर से कर्ज का यह बोझ कब समाप्त होगा। पहले पूर्व



मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 सालों तक 04 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज प्रदेश पर छोड़ा है। वहीं, अब मोहन सरकार लगातार कर्ज लेकर प्रदेश के विकास की इबारत लिखने की तैयारी में है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब आरबीआई और विश्व बैंक प्रदेश की जनता से इन करोड़ों रुपये के उधार का कर्ज वसूल करने के लिये आतुर हो जायेगा। जानकारी के मुताबिक मोहन सरकार 5000 हजार करोड़ का कर्ज दो बार में ढाई-ढाई हजार करोड़ रुपये के रूप में लेगी। वित्त विभाग ने नए लोन के लिए ऑक्शन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। विभाग ने कहा है कि ढाई हजार-ढाई हजार करोड़ का यह कर्ज 28 अगस्त 2038 तक 14-14 साल की अवधि के लिए लिया जा रहा है। इसका ब्याज सरकार हर साल जमा करती रहेगी। (शेष पेज 7 पर)

# दबंग किसान के बेटे ने कार से टक्कर मार, चार लोगों को जान से मारने की कोशिश की

-अमित राजपूत

जगत प्रवाह, सागर। देवरी

थाना अंतर्गत ग्राम घुघरी में एक दबंग किसान के बेटे ने चार लोगों को कार से टक्कर मार दी। ग्राम घुघरी निवासी घायल मनोज दुबे ने बताया मैं सुबह 10:30 बजे खेत से घर जा रहा था तो रास्ते में श्याम सुंदर कटारे का मजला लड़का मुझे देखते हुए गया। कुछ देर बाद देवरी से मेरे बड़े भाई आ गए इतने सेंट्रो कार राहुल कटारे ने रास्ते में से मोड़ कर मुझे एवं मेरे बड़े भाई को टक्कर मार दी और कार को आगे पीछे करके मुझे जान जमाने की कोशिश की। वहीं पास में भूरे आदिवासी और बंदू आदिवासी उनको भी मारने की कोशिश की जिसमें एक ही गांव के चार



लोग घायल हो गए घायल लोगों ने और ग्रामीणों ने थाना देवरी आकर राहुल कटारे के ऊपर मामला दर्ज करवाया। जिसमें 296,115(2),315(2) ,109,324(4),324(6),3(1)(द),3(1)(ध),3(2)(v)3(2)(VA) धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। (जगत फीचर्स)

# सतपुड़ा गो अभ्यारण्य का कलेक्टर आदित्य सिंह ने किया निरीक्षण



-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह, टिम्नरी। दिनांक 14 सितंबर को हरदा जिला कलेक्टर आदित्य सिंह ने टिम्नरी क्षेत्र का दौरा किया। टिम्नरी नगर में उन्होंने बांस बंसी एंगोरियम, शासकीय अस्पताल एवं छात्रावास का निरीक्षण किया। इसके पश्चात टिम्नरी से लगभग 20 किलोमीटर दूर बैतूल मार्ग पर उसकल्ली कपासी फूटान पर स्थित सतपुड़ा गो अभ्यारण्य का भी निरीक्षण किया। यहां उन्होंने सर्वप्रथम गो माता की पूजा अर्चना की। संचालन कर्ताओं से यहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली इस दौरान संचालन कर्ताओं ने डीएम साहब को बताया कि यह फॉरेस्ट की भूमि है यहां वगैर पेड़ काटे ही इसके अंदर छोटे-छोटे सेंड गो माता के लिए बनवा दिये जाए और यहां मरुम डलवाई जाए ताकि बारिश में गौवंश को कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने बताया कि यहां लगभग 20 एकड़ में अभी जाली फेंसिंग की व्यवस्था है और यहां से चार से पांच किलोमीटर दूर गंजाल नदी की ओर चरने जाती हैं वहां तक सड़क किनारे जाली फेंसिंग की व्यवस्था करवाई जाए। इस दौरान ग्राम उसकल्ली कपासी गांव के लोगों ने यहां संचालित को अभ्यारण्य का विशेष करते हुए एक आवेदन कलेक्टर को दिया जिसमें उन्होंने बताया कि यहां की गो माताएं हमारे गांव में जाकर बैठती हैं खेतों में नुकसान करती हैं और जो मर जाती है तो उनकी बच्ची आती है उन्हें कोई उठाने वाला नहीं रहता। इस प्रकार लोगों ने अपनी आप बीती सुनाते हुए कलेक्टर से निवेदन किया कि यहां से सतपुड़ा गो अभ्यारण्य को हटाया जाए ताकि हमारे खेत और यहां के गंजल में जो पौधे लगे हुए हैं उन्हें भी नुकसान ना हो। इस दौरान एसडीएम महेश बड़ोले रहटोयंग तहसीलदार जनपद सीईओ एसडीओ रंजर फारेस्ट पुलिस बल सहित बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित रहे। (जगत फीचर्स)

# श्री श्री गणपति पूजा समिति ने मनाया रजत जयंती महोत्सव

-अमित राय

जगत प्रवाह, हवड़ा। ओड़िया पाड़ा, "श्री श्री गणपति पूजा समिति" वर्ष 2024 में अपना रजत जयंती महोत्सव मनाया। वर्ष 2000 से शुभारंभ हुई धार्मिक अनुष्ठान (श्री गणेश पूजा), वर्ष दर वर्ष होते हुए इस वर्ष अपना 25वां साल पूरा करते हुए संस्था द्वारा रजत जयंती महोत्सव को विशेष रंगों में रंगने का भरपूर प्रयास किया गया। जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे कि नृत्य-संगीत, महाभोग प्रसाद आदि ने लोगों को आकर्षित किया। वहीं भगवान श्री गणेश की प्रतिमा व पूजा मण्डप भी आकर्षण का केन्द्र बना रहा। रजत जयंती के विशेष अवसर पर रविवार 8 सितंबर, 2024 को इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (IFWJ), इंडिया इनसाइड न्यूज (indianside.org),



जगत विज्ञान पत्रिका व जगत प्रवाह अखबार की ओर से पत्रकार अमित राय तथा महरोर डिजिटल व महरोर फाउंडेशन की ओर से अनुप कुमार सिंह द्वारा श्री श्री गणपति पूजा समिति को मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया और इस विशेष उपलब्धि के लिए बधाई दी गई। वहीं संस्था के समन्वयक विशाल जयसवाल तथा चैयरमैन एडवोकेट राम चन्द्र अग्रवाल ने बताया कि 9 सितंबर को संध्या 8 बजे से महाभोग प्रसाद का वितरण हुआ जिसमें सैकड़ों लोग सम्मिलित हुए और प्रभु श्री गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त किए। बता दें कि पूजा मण्डप उद्घाटन समारोह का आयोजन शुक्रवार 6 सितंबर को विशेष अतिथियों की मौजूदगी में हुआ। वहीं दीप प्रज्वलित इस्कॉन, कोलकाता के श्रीमान महारास दास द्वारा किया गया। (जगत फीचर्स)

# स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत एम्स में रोगियों एवं स्वास्थ्यकर्मियों के लिए खाद्य स्वच्छता, पोषण जागरूकता, और स्वच्छता अभियान का आयोजन

-दुर्गेश अरमोती

जगत प्रवाह, भोपाल। एम्स

भोपाल ने "स्वच्छता ही सेवा" अभियान के अंतर्गत 21 सितंबर 2024 को एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक और सीईओ प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के मार्गदर्शन में आहार विभाग द्वारा खाद्य स्वच्छता और पोषण पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही विभिन्न विभागों में कचरे की पहचान और उसे स्क्रेप/नट करने की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया गया। इस संदर्भ में स्वच्छता

गतिविधियों और स्वच्छता अभियान भी चलाया गया, जिसमें विभिन्न विभागों में स्वच्छता को बढ़ावा देना और संक्रमण की रोकथाम सुनिश्चित करने हेतु इस विशेष सप्ताह अभियान में सभी ने अपना सक्रिय योगदान दिया तथा स्वच्छता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त किया। कार्यपालक निदेशक और सीईओ प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित इस पहल का उद्देश्य न केवल स्वच्छता और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना था, बल्कि कर्मचारियों और मरीजों को स्वच्छ और पोषित भोजन के महत्व से भी

अवगत कराना था। इस आयोजन में सभी विभागों ने स्वच्छता और स्वच्छता ही सेवा अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस अवसर पर स्वस्थ भोजन, मोटे अन्न (मिल्लेट्स डाइट) का वितरण रोगियों एवं आगतुक्त में भी किया गया तथा आहार विशेषज्ञ द्वारा मरीजों, कर्मचारियों और उपस्थित लोगों को पीपिटिक आहार के महत्व के बारे में जानकारी प्रदान की गई। इसमें बताया गया की स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ एवं पोषित भोजन अत्यंत आवश्यक है। (जगत फीचर्स)



# प्राधिकरण में अब सभी मंत्री होंगे सदस्य: पांचों विकास प्राधिकरणों के पुनर्गठन को साय कैबिनेट से मंजूरी, शहरी विकास नीति भी बनेगी

## -संवाददाता

**जगत प्रवाह.** रायपुर। छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट की बैठक में कई आहम फैसले लिए गए हैं। प्रदेश के 5 विकास प्राधिकरणों के पुनर्गठन के आदेश को हरी झंडी मिल गई है। इस संशोधन से पांचों प्राधिकरणों में जनप्रतिनिधियों का दायरा बढ़ेगा। वहीं, कैबिनेट बैठक में शहरी विकास नीति तैयार करने को भी मंजूरी मिली है। इससे शहरों के विकास और राज्य की विकास योजनाओं को लागू करने का काम होगा। इसके दिशा-निर्देश जारी करने के लिए आवास एवं पर्यावरण विभाग को जिम्मा दिया गया है।

## शहरी विकास नीति में ये काम होंगे

इस स्कीम से अतिक्रमण, अवैध निर्माण पर रोक लगाने का काम होगा। शहरी आबादी को सुविधाएं देने और उनकी समस्या दूर करने के काम होंगे। नगर विकास योजना में आवासीय, कॉमर्सियल और इंडस्ट्रियल यूज लैंड को लेकर नियम जारी होंगे।

## प्राधिकरण पुनर्गठन से क्या होगा?

छत्तीसगढ़ में 5 विकास प्राधिकरण हैं। हर प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। साथ ही दो मंत्रियों की जगह अब पूरा मंत्रिमंडल इसमें शामिल होगा। इसके अलावा जिस इलाके का प्राधिकरण है वहां के राज्यसभा, लोकसभा के सांसद और जिला पंचायत अध्यक्ष को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

कैबिनेट के अन्य फैसले मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान मद से 262 व्यक्ति और संस्थाओं को 4 करोड़ 56 लाख 72 हजार रुपए स्वीकृत राशि का अनुमोदन किया गया है।

## वित्त विभाग से 181 पदों पर भर्ती का फैसला

कैबिनेट बैठक के फैसलों के अलावा शुक्रवार को वित्त विभाग ने भी बड़ा फैसला लिया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में इंजीनियर्स सहित बाकी पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले से 181 रिक्त पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। नई भर्ती से विभाग के कामकाज की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ पेयजल व्यवस्था बेहतर की जाएगी।



## इन पदों पर भर्ती को मंजूरी

पीएचडी विभाग में 3 उप अभियंता, अनुपेक्षक, सहायक गेड-3 सहित बाकी खाली पदों को भरने के प्रस्ताव को वित्त विभाग से स्वीकृति

मिली है।

उप अभियंता (सिविल) के 118 उप अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी) के 10 अनुपेक्षक के 37

सहायक गेड-3 के 02

कैमिस्ट के 12  
वाहन चालक के 2 उप शामिल है।  
(जगत फीचर्स)

# साय सरकार का बड़ा फैसला, 46% तक बढ़ाई डॉक्टरों-प्रोफेसरों की सैलरी

## -संवाददाता

**जगत प्रवाह.** रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने मेडिकल कॉलेज स्टाफ को सैलरी में ऐतिहासिक बढ़ोतरी करके बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने छत्तीसगढ़ के शासकीय मेडिकल कॉलेजों के सीनियर रेजिडेंट से लेकर प्रोफेसरों की सैलरी बढ़ा दी है। गैर अनुसूचित क्षेत्रों में 1 लाख 90 हजार रुपये वेतन मिलेगा। अनुसूचित क्षेत्रों में वेतन में लगभग 46 फीसदी और गैर अनुसूचित क्षेत्रों में लगभग 23 फीसदी बढ़ोतरी की जा रही है।

## 1 सितंबर से मिलेगी बड़ी हुई इतनी सैलरी

नया वेतन राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 1 सितंबर 2024 से लागू होगा। छत्तीसगढ़ चिकित्सा

शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, महत्वपूर्ण वेतन वृद्धि की गई है। उदाहरण के लिए, गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में प्रोफेसरों का वेतन 1.55 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.90 लाख रुपये कर दिया गया है, जबकि अनुसूचित क्षेत्रों में वेतन 1.90 लाख रुपये से बढ़कर 2.25 लाख रुपये हो गया है। एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर और सीनियर रेजिडेंट के लिए वृद्धि हुई है।

छत्तीसगढ़ शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, गैर अनुसूचित क्षेत्रों के मेडिकल कॉलेज में पदस्थ प्राध्यापक का वेतन एक लाख 55 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख 90 हजार रुपये कर दिया गया है। इसी तरह सह प्राध्यापक का

वेतन एक लाख 35 हजार से एक लाख 55 हजार, सहायक प्राध्यापक का वेतन 90 हजार से एक लाख तथा सीनियर रेजिडेंट का वेतन 65 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि अनुसूचित क्षेत्रों के मेडिकल कॉलेज में पदस्थ प्राध्यापक का वेतन एक लाख 90 हजार रुपये से बढ़ाकर दो लाख 25 हजार रुपये कर दिया गया है। इसी तरह सह प्राध्यापक का वेतन एक लाख 55 हजार से एक लाख 85 हजार, सहायक प्राध्यापक का वेतन 90 हजार से एक लाख 25 हजार तथा सीनियर रेजिडेंट और प्रदर्शक (पीजी) का वेतन 65 हजार रुपये से बढ़ाकर 95 हजार रुपये कर दिया गया है।

46 फीसदी तक हुई वेतन में बढ़ोतरी उन्होंने बताया कि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के संविदा

चिकित्सकों के लिए जारी पुनरीक्षित संविदा वेतनमान के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में लगभग 46 फीसदी तथा गैर अनुसूचित क्षेत्र में लगभग 23 फीसदी की वेतन बढ़ोतरी की गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने वेतन वृद्धि पर कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में पढ़ने वाले भावी चिकित्सकों का ये अधिकार है कि उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाला शिक्षक और शिक्षा मिले तथा वेतन में बढ़ोतरी का यह आदेश राज्य शासन की स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने की मंशा को स्पष्ट जाहिर करता है। (जगत फीचर्स)



# कवर्धा हत्याकांड में सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा एक्शन, कलेक्टर-एसपी का ट्रांसफर, पूरे थाने को किया सरपेंड

## -संवाददाता

**जगत प्रवाह.** रायपुर। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में प्रशांत साहू हत्याकांड पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने कवर्धा जिले के एसपी और कलेक्टर को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। वहीं कवर्धा कांड की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए हैं। सरकार ने कबीरधाम जिले के एसपी अभिषेक पल्लव और कलेक्टर जन्मेजय महोबे को हटा दिया गया है। गोपाल वर्मा को कबीरधाम का नया कलेक्टर बनाया गया है। वहीं, राजेश कुमार अग्रवाल को जिले का एसपी नियुक्त किया गया है।

## पूरे थाने को किया सरपेंड

सीएम साय ने कवर्धा जिले में ग्राम लोहारीडीह में 15 सितंबर को शिवप्रसाद साहू की मौत के बाद घटित आगजनी में रघुनाथ साहू की मृत्यु की दुर्भाग्यजनक घटना के मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इस घटना के परिप्रेक्ष्य में पुलिसकर्मियों द्वारा ग्रामीणों से मारपीट किए जाने की घटना के चलते रेंगाखार थाने के निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक सहित वहां पदस्थ कुल 23 पुलिसकर्मियों को भी हटा दिया है।

## कड़ी कार्रवाई की जाएगी

मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कबीरधाम द्वारा अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी निर्भय कुमार साहू

को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्हें 30 दिनों के अंदर पूरे घटना की रिपोर्ट सौंपनी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव ने कहा कि भविष्य में इस तरह की किसी भी प्रकार की घटना में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा संबंधितों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

## रायपुर बुलाए गए अभिषेक पल्लव

कवर्धा एसपी अभिषेक पल्लव को रायपुर बुलाया गया है। अभिषेक पल्लव को सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ में पदस्थ किया गया है। वहीं बीजापुर जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बैकर वैभव को बलरामपुर जिले का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है।

## व्या है मामला

दरअसल, 15 सितंबर को कवर्धा जिले के लोहारीडीह में पत्थरबाजी और आगजनी की गई थी। इस घटना में उपसरपंच रघुनाथ साहू की मौत हो गई थी। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया था। इस दौरान ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने बर्बर तरीके से लोगों को पिटाई की। इसके वीडियो भी वायरल हुए थे। मामले में नया मोड तब आया जब एक इस मामले में एक आरोपी प्रशांत साहू की जेल में ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।

(जगत फीचर्स)

## सम्पादकीय

## तिरुपति मंदिर पर इतने वर्षों बाद अचानक जंग छिड़ने के पीछे क्या मायने ?

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा तिरुपति मंदिर के लड्डू पर किए गए खुलासे ने नई बहस छेड़ दी है। लड्डू बनाने के लिए अशुद्ध घी के इस्तेमाल के लिए जगनमोहन रेड्डी की तत्कालीन सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लड्डू बनाने वाले घी में मछली का तेल, सुअर और गाय की चर्बी मिलाए जाने की बात सामने आने के बाद लोगों की भावनाएं भी आहत हुई हैं। यह मुद्दा इसलिए भी गरमाया है क्योंकि तिरुपति मंदिर का प्रसादम पूरे देश में अपने अलग स्वाद के लिए जाना जाता है। यह पूरा मामला तब चर्चा में आया जब मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक लेब रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि, प्रसिद्ध तिरुपति लड्डू बनाने में पशु मांस का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि, राज्य

में पिछली वॉर्देसआरसीपी सरकार के दौरान प्रसिद्ध तिरुपति लड्डू बनाने में घटिया सामग्री और पशु वसा का इस्तेमाल किया गया था। सीएम ने एक लेब टेस्ट रिपोर्ट का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि, टेस्ट रिपोर्ट से पता चलता है कि, तिरुपति के प्रसिद्ध वेंकटेश्वर मंदिर में प्रसाद के रूप में वितरित किए जाने वाले लड्डू ब्रे बनाने के लिए गोमांस की चर्बी, मछली के तेल और ताड़ के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आश्वासन दिया कि, तिरुमाला लड्डू में पशु वसा की मिलावट के मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की

जाएगी। उन्होंने कहा कि, पिछली सरकार ने तिरुमाला में प्रसाद को नष्ट कर दिया था और टीटीडीपी सरकार ने पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए सुधार कार्य शुरू किए हैं। दरअसल, टीटीडीडी बोर्ड हर साल लगभग पांच लाख किलो घी खरीदता है। इस हिस्सा से हर महीने लगभग 42,000 किलोग्राम घी खरीदा जाता है। घी की खरीद के लिए हर 6 महीने में टेंडर जारी किया जाता है। घी के अलावा टीटीडीडी को लगभग 22,500 किलोग्राम कजु, 15,000 किलोग्राम किरामिश और 6,000 किलोग्राम इलायची की भी जरूरत होती है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि, पहले कर्नाटक मिल्क फेडरेशन द्वारा घी की आपूर्ति की जाती थी। चार साल पहले आपूर्ति बंद कर दी गई थी। इसका कारण था घी की कीमत। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के अनुसार घी की कीमत को लेकर विवाद हुआ था इसके बाद सप्लाय बंद कर दी गई। रिपोर्ट्स के अनुसार कर्नाटक मिल्क फेडरेशन की कंपनी नंदिनी, टीटीडी को कम कीमत पर घी देने में असमर्थ था। इसका कारण थी कांग्रेस शासित कर्नाटक सरकार। कांग्रेस शासित कर्नाटक सरकार ने दूध की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी का आदेश दिया था। इस बीच, रिपोर्ट्स में कहा गया है कि तिरुपति मंदिर बोर्ड ने तमिलनाडु के डिंडीगुल के एक आपूर्तिकर्ता की ओर रुख किया, जिसके घी में कथित तौर पर पशु वसा के अंश पाए गए।



## सियासी गहमागहमी

## सदस्यता अभियान में हीरो बनने की लगी होड़



मध्यप्रदेश भाजपा के विधायक इन दिनों सदस्यता अभियान में हीरो बनने की होड़ में लगे हुए हैं। यही कारण है कि सोशल मीडिया से लेकर स्थानीय व मोबाइल फोन, एसएमएस सहित अनेकों तरह के वीडियो प्रमोशन में विधायकगण जुटे हुए हैं। अभियान में हीरो बनने की होड़ में माननीय यह तक भूल गये हैं कि कई विधानसभा क्षेत्रों में जनता सड़क के गड्ढों से जुड़ा रही है तो कहीं दूसरी अन्य समस्याएं हैं जिनका माननीय को ख्याल तक नहीं है। उदाहरण के तौर पर भोपाल की ही बात करें तो नरेला हो या फिर भोपाल परिश्रम, हुजूर सभी स्थानों पर बारिश के बाद सड़कों के बदहाल हाल ने आमजनता को पूरी तरह से परेशान कर दिया है। लेकिन माननीय पूरी तरह से सदस्यता अभियान में जुटे हुए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वे सदस्यता अभियान में सक्रिय रहे तो उनका मंत्रीपद बचा रहेगा और कुछ को मंत्री पद मिल जायेगा। अब देखने वाली बात यह है कि मोहन सरकार इस पूरे मामले को कैसे देखती है और किस माननीय को क्या उपहार देती है।

## अखिर कब खत्म होगा आपसी खींचतान का यह दौर



मध्यप्रदेश में कांग्रेस पार्टी इन दिनों बड़े पशोपेश में फंसी हुई है। पार्टी के नेता एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां वे प्रदेश अध्यक्ष के सामने न तो अपनी बात रख पा रहे हैं और न ही उन्हें कुछ कह पा रहे हैं। आलम यह है कि कार्यकर्ता से लेकर नेता तक सभी एक दूसरे से अपनी गुहार लगाकर खुद को सांत्वना देने में जुटे हैं। चर्चा इस बात की है कि प्रदेश अध्यक्ष साहब जीतू पटवारी को न तो पार्टी के कार्यकर्ता से मतलब है और न ही नेता से। वे पूरी तरह से अपनी राजनीतिक जमावट में लगे हुए और दबे पांव मलाई खाने की भाजपा नेताओं के साथ जुगत बैठा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि पटवारी साहब का यह रोल कांग्रेस आलाकमान कब तक देखती है या फिर उन पर कोई एक्शन कर बड़ी कार्यवाही की जायेगी।

## हपते का कार्टून



## ट्वीट-ट्वीट

ओडिशा में घटित भयंकर घटना ने देश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पुलिस से मदद मांगने गए एक सेना अधिकारी को बेरहमी से पीटा गया और उनकी मंगेतर को कस्टडी में उतरीकित किया गया। यह घृणित घटना पूरी मानवता को शर्मसार करने वाली है।

-राहुल गांधी

कांग्रेस नेता @RahulGandhi



बागेश्वर धाम पहुँचकर हमेशा ही दिव्य और अलौकिक अनुभूति होती है। आज फिर प्रभु हनुमान जी के दर्शन करने एवं पंडित धीरेट कृष्ण शारसी जी से मुलाकात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

-कमलनाथ

पेट्टे कावेस अय्यर

@OfficeOfKNath



राजवीरों की बात

आम आदमी पार्टी की नई  
नायक बन दिल्ली की सत्ता  
पर काबिज हुई आतिशी

समता पाठक/जगत प्रवाह



आम आदमी पार्टी की एक गतिशील राजनीतिज्ञ आतिशी मार्लेना दिल्ली के शिक्षा क्षेत्र में अपने नेतृत्व से प्रमुखता से उभरी हैं। दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने प्रमुख शैक्षिक सुधारों की शुरुआत की, शिक्षकों को सशक्त बनाया और छात्र कल्याण की वकालत की, जिससे वह आधुनिक भारतीय राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति बन गईं। 8 जून 1981 को जन्मी आतिशी मार्लेना एक प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञ और दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, जो आम आदमी पार्टी (आप) का प्रतिनिधित्व करती हैं। वह दिल्ली मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला और भारत में सबसे कम उम्र की वर्तमान मुख्यमंत्री होने के लिए उल्लेखनीय हैं। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी के माता-पिता, विजय सिंह और तुप्ता वाही, दोनों दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में काम करते थे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा नई दिल्ली के स्प्रिंगडेल्स स्कूल से पूरी की और 2001 में सेंट स्टीफन कॉलेज, नई दिल्ली से इतिहास में प्रथम श्रेणी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने 2003 में शेवर्निंग छात्रवृत्ति पर अपनी पहली मास्टर डिग्री हासिल की। 2005 में, उन्होंने रोड्स स्कॉलर के रूप में शैक्षिक अनुसंधान में अपनी दूसरी मास्टर डिग्री हासिल की।

आतिशी जनवरी 2013 में आम आदमी पार्टी (आप) में शामिल हुईं और नीति-निर्माण और सक्रियता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाईं। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान उन्हें प्रसिद्धि मिली और उन्होंने मध्य प्रदेश में जल सत्याग्रह जैसे कार्यक्रमों में भाग लिया। 2019 में, उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन भाजपा के गैतम गंधीर से हार गईं। हालाँकि, उन्होंने 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में कालकाजी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की, और अपने प्रतिद्वंद्वी को 11,000 से अधिक मतों से हराया। यहां उनके करियर की कुछ प्रमुख उपलब्धियाँ हैं। आतिशी को दिल्ली की पब्लिक स्कूल प्रणाली में शिक्षा परिवर्तन के प्रति उनके दृष्टिकोण के लिए सबसे लोकप्रिय जाना जाता है। उन्होंने "मिशन बुनियाद" की शुरुआत की जिसका मुख्य लक्ष्य छात्रों की सीखने की साक्षरता और संख्यात्मक दक्षताओं को बढ़ाना है। वह 'हेपीनेस करिकुलम' और 'एंटरेप्रेन्योरशिप माईडसेट करिकुलम' जैसे नए पाठ्यक्रम भी लेकर आईं; जो छात्रों के कल्याण में सुधार और उनकी क्षमताओं को विकसित करने के लिए हैं। उनके कार्यकाल के दौरान, शिक्षा पर व्यय में काफी वृद्धि हुई, जिससे दिल्ली के सरकारी स्कूलों को अपने बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में सुधार करने में मदद मिली। आतिशी ने शिक्षकों के प्रशिक्षण में सुधार करने का प्रयास किया है ताकि शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए बेहतर स्थिति में हों। इसने दिल्ली के विभिन्न स्कूलों में होने वाली शिक्षण की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाने में भी बड़ी भूमिका निभाई है।

उन्होंने ऐसे एजेंडे का समर्थन किया है जो शिक्षार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें और यहां तक कि वर्दी वितरित करता है, जिसने छात्रों के लिए वर्दी की लागत को कम करने में काफी मदद की है जिससे स्कूल में उपस्थिति को बढ़ावा मिला है। वर्तमान में, आतिशी दिल्ली सरकार में वित्त, शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, बिजली और पानी जैसे 14 महत्वपूर्ण विभागों को संभालती हैं। यह व्यापक जिम्मेदारी दराशांती है कि वह कैबिनेट में कितनी शामिल हैं और सत्ता के विभिन्न पहलुओं को संभालने में एक नेता के रूप में उनकी क्षमता को दर्शाती है।

छिंदवाड़ा में कांग्रेस को नए सिरे से संगठित करने में जुटे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ

-समता पाठक

जगत प्रवाह, भोपाल। छिंदवाड़ा में आज पांडुरंगा, सौर और अमरवाड़ा विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कमलनाथ ने समीक्षा बैठक की। कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं से पूरे उत्साह के साथ जनता के मुद्दे उठाने की अपील की। कमलनाथ ने कहा कि वह और नकुल नाथ पहले की तरह ही छिंदवाड़ा में पूरी सक्रियता से कार्य करेंगे। छिंदवाड़ा की जनता की सेवा करना ही उनके जीवन का उद्देश्य है। कमलनाथ के साथ पूर्व सांसद नकुलनाथ एवं छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के विधायकगण भी बैठक में उपस्थित रहे। छिंदवाड़ा और पांडुरंगा जिलों की कांग्रेस कमेटीयां पहले ही भंग की जा चुकी है। छिंदवाड़ा के दो दिन प्रवास के बाद भोपाल में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे।



श्री विष्णु देव साव  
माननीय मुख्यमंत्री  
छत्तीसगढ़ शासन



छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड की  
उपलब्धियां



श्री राम बिचार नेताम  
माननीय कृषि मंत्री  
छत्तीसगढ़ शासन

- ❖ गौ-सेवा आयोग को वृद्ध पशुओं की देखभाल तथा गौ-शालाओं के संरक्षण हेतु वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 तक रु. 88.71 करोड़ का अनुदान दिया गया।
- ❖ फल-सब्जी उपमंडी :- प्रदेश में बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, धमतरी, पखांजूर, तथा उपमंडी धमधा में फल-सब्जी का क्रय-विक्रय हो रहा है।
- ❖ राष्ट्रीय कृषि बाजार :- प्रदेश की 20 मंडियां राष्ट्रीय कृषि बाजार से जुड़ी हुई हैं।
- ❖ गोदाम :- कृषकों की कृषि उपज के वैज्ञानिक ढंग से भण्डारण हेतु प्रदेश की मंडी समितियों में 3.52 लाख मेटन क्षमता के 447 गोदाम हैं।
- ❖ मंडी बोर्ड द्वारा प्रदेश में 227 हाट-बाजार रु. 108.25 करोड़ की लागत से स्वीकृत।
- ❖ मंडी बोर्ड द्वारा राज्य विपणन विकास निधि से प्रदेश के विभिन्न मंडी क्षेत्रों में पुल-पुलिया के रु. 46.69 करोड़ के 105 कार्य स्वीकृत है।
- ❖ मंडी बोर्ड द्वारा प्रदेश की विभिन्न मंडी/उपमंडी प्रांगण में गोदाम के रु. 63.55 करोड़ के लागत से 1.48 लाख मेटन क्षमता के 114 गोदाम स्वीकृत है।
- ❖ मंडी बोर्ड द्वारा राज्य विपणन विकास निधि एवं मंडी समिति निधि से प्रदेश की प्राथमिक कृषि सहकारी समिति में 587 किसान कुटीर रु. 82.18 करोड़ की लागत से स्वीकृत हैं।
- ❖ फल सब्जी उपमंडी गण्डई में रु. 12.16 करोड़ की लागत से स्वीकृत समी 20 कार्य प्रगतिरत, फल सब्जी मंडी कुनकुरी में रु. 2.72 करोड़ की लागत से स्वीकृत 8 कार्य प्रगतिरत, फल सब्जी मंडी कुसमी में रु. 4.84 करोड़ के लागत से स्वीकृत समी 12 कार्य प्रगतिरत।
- ❖ नवीन उपमंडी प्रांगण भाटापारा में 54.27 करोड़ की लागत से स्वीकृत 21 कार्या हेतु निविदा आमंत्रित की गई है।
- ❖ जशपुर जिला अंतर्गत 46 धान उपाजर्न केन्द्रों में रु. 39.58 करोड़ की लागत से विभिन्न निर्माण कार्यों की निविदा आमंत्रित की गई है।

छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड

सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन, सेक्टर -24, कयाबाधा, अटल नगर,  
नवा रायपुर- 492018

# 2029 में एक-देश, एक-चुनाव संयुक्त चुनाव कराने की तैयारी



प्रमोद भार्गव

2029 में एक देश, एक चुनाव, यानी देश में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के साथ निकाय व पंचायत चुनाव भी एक साथ कराने की स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी है। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के सौ दिन पूरे होने पर गृहमंत्री अमित शाह ने आत्मविश्वास के साथ कहा है कि 2029 के पहले एक साथ चुनाव का प्रबंध कर दिया जाएगा। साफ है, सरकार अपने इस महत्वाकांक्षी वादे को क्रियान्वित करने के प्रति संकल्पबद्ध है। इसी क्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट की अनुशंसाओं को भी कैबिनेट ने मंजूर कर लिया। साफ है, केंद्र सरकार ने विपक्षी दलों को स्पष्ट संकेत दे दिया है कि सरकार अपने अजेंडे पर आगे बढ़ती रहेगी। उम्मीद है कि शीतकालीन सत्र में एक देश एक चुनाव कराने के नजरिए से शीतकालीन सत्र में इस विधेयक और इस प्रक्रिया को पूरी करने वाले संशोधन विधेयकों को पारित कराने की शुरुआत संसद में हो जाएगी। हालांकि कांग्रेस समेत करीब 15 राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि भाजपा समेत 32 राजनीतिक दल इसके समर्थन में हैं।

एक साथ चुनाव कराने जाते हैं तो इस समय जिन राज्य सरकारों का कार्यकाल बचा होगा, वह लोकसभा चुनाव तक ही पूरा मान लिया जाएगा। वैसे भी आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ होते रहे हैं, लेकिन 1968 और 1969 में समय के पहले ही कुछ राज्य सरकारों भंग कर दिए जाने से यह परंपरा टूट गई। अब इस व्यवस्था को लागू करने के लिए संविधान में करीब 18 संशोधन करने होंगे। इनमें से कुछ बदलावों के लिए राज्यों की भी अनुमति जरूरी होगी। यदि स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव भी साथ साथ होते हैं तो फिर मतदाता सूची तैयार निर्वाचन आयोग कराएगा। इस हेतु अनुच्छेद 325 में परिवर्तन करना होगा। साथ ही अनुच्छेद 324 ए में संशोधन करते हुए निगमों और पंचायतों के चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ करा लिए जाएंगे। संविधान के अनुच्छेद 368 ए के तहत इस संशोधन विधेयक को आधे राज्यों से भी पास करना जरूरी होगा। इसी अनुरूप केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी अलग से

संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी।

इस रिपोर्ट से पहले संसदीय समिति भी देश में एक साथ चुनाव कराने की वकालत कर चुकी थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि यदि लोकसभा, विधानसभा, नगरीय निकायों और पंचायतों के चुनाव एक साथ होते हैं तो लंबी चुनाव प्रक्रिया के चलते मतदाता में जो उदासीनता छा जाती है, वह दूर होगी। एक साथ चुनाव में वोट डालने के लिए मतदाता को एक ही बार घर से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचना होगा, अतएव मतदान का प्रतिष्ठत बढ़ जाएगा। यदि यह स्थिति बनती है तो चुनाव में सरकारी धन कम खर्च होगा। 2019 के आम चुनाव में करीब 60,000 करोड़ खर्च हुए थे और 2024 के चुनाव में लगभग एक लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। एक साथ चुनाव में राजनीतिक दल और प्रत्याषी को भी कम धन खर्च करना होगा। दरअसल अलग-अलग चुनाव होने पर हराने वाले कई प्रत्याषी एक बार फिर किस्मत आजमाने के मूड में आ जाते हैं, वहीं विधायकों को भी लोकसभा और सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में जो सीट खाली होती है, उसे फिर से छह माह के भीतर भरने की संवैधानिक बाध्याता के चलते चुनाव करना पड़ता है। नतीजतन जनता के साथ-साथ प्रत्याषी को भी चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी उदासीनता झेलनी पड़ती है। इस कारण सरकारी मशीनों की जहां कार्य संस्कृति प्रभावित होती है, वहीं मानव संसाधन का भी ह्रास होता है।

चूंकि संविधान के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकारें अलग-अलग इकाइयां हैं। इस परिप्रेक्ष्य में संविधान में समानांतर किंतु भिन्न-भिन्न अनुच्छेद हैं। इनमें स्पष्ट उल्लेख है कि इनके चुनाव प्रत्येक पांच वर्ष के भीतर होने चाहिए। लोकसभा व विधानसभा जिस दिन से गठित होती है, उसी दिन से पांच साल के कार्यकाल की गिनती शुरू हो जाती है। इस लिहाज से संविधान विशेषज्ञों का मानना है कि एक साथ चुनाव के लिए कम से कम 18 अनुच्छेदों में संशोधन किया जाना जरूरी होगा। विधि आयोग, निर्वाचन आयोग, नीति आयोग और संविधान समीक्षा आयोग तक इस मुद्दे के पक्ष में अपनी राय दे चुके हैं। ये सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं। यदि विपक्षी दल सहमत हो जाते हैं तो दो तिहाई बहुमत से होने वाले ये संशोधन कठिन कार्य नहीं हैं। 2024 में मोदी सरकार की बहाली हो गई है, इससे एक साथ चुनाव की उम्मीद बढ़ गई है। इस दौरान

ईवीएम समेत अन्य चुनावी उपकरणों की जरूरत पूरी कर ली जाएगी।

अनेक असमानताओं, विसंगतियों और विरोधाभासों के बावजूद भारत एक संस्कृतिक राष्ट्रवाद के सूत्र से बंधा है। निर्वाचन प्रक्रिया राष्ट्र को एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था देती है, जिससे भिन्न स्वभाव वाली राजनीतिक शक्तियों को केंद्रीय व प्रांतीय सत्ताओं में भागीदारी का अवसर मिलता है। नतीजतन लोकतांत्रिक प्रक्रिया गतिशील रहती है, जो देश की अखंडता व संप्रभुता के प्रति जवाबदेह है। देश में मानव संसाधन सबसे बड़ी पूंजी हैं। गोया, यदि बार-बार चुनाव की स्थितियां बनती हैं तो मनुष्य का ध्यान बंटता है और समय व पूंजी का क्षरण होता है। इस दौरान आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के कारण प्रशासनिक शिथिलता दो-ढाई महीने तक बनी रहती है, फलतः विकास कार्य और जन-कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित होती हैं। एक साथ चुनाव के चलते सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षा बलों को बार बार चुनाव ड्यूटी का मानसिक तनाव नहीं झेलना पड़ेगा।

एक साथ चुनाव के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि देश प्रत्येक छह माह बाद चुनावी मूड में आ जाता है, लिहाजा सरकारों को नीतिगत फैसले लेने में तो अड़चनें आती ही हैं, दूसरे नीतियों को कानूनी रूप देने में अतिरिक्त विलंब भी होता है। यह तर्क अपने ही जगह जायज है। वैसे भी राजनीतिक दलों की महत्ता तभी है जब वे नीतिगत फैसलों को अधिकतम लोकतांत्रिक बनाने के लिए अपने सुझाव दें व उन्हें विधेयक के प्रारूप का हिस्सा बनाने के लिए नैतिक दबाव बनाएं। ऐसा नहीं है कि एक साथ चुनाव का विचार कोई नया विचार है। 1952 से लेकर 1967 तक चार बार लोकसभा व विधानसभा चुनाव पूरे देश में एक साथ ही हुए हैं। इंदिरा गांधी का केंद्रीय सत्ता पर वर्चस्व कायम होने के बाद राजनीतिक विद्वेष व बेजा हस्तक्षेप के चलते इस व्यवस्था में बदलाव आना शुरू हो गया। इंदिरा गांधी को विपक्ष की जो सरकार पसंद नहीं आती थी, उसे वे कोई न कोई बहाना ढूंढकर अनुच्छेद-356 के तहत राष्ट्रपति से बर्खास्त करा देती थीं। नतीजतन मध्यावधि चुनावों की परिपाटी पड़ती चली गई। इससे राज्यों में अलग-अलग समय पर चुनाव कराने की बाध्याता निर्मित हो गई। अयोध्या में विवादित ढांचा ध्वस्त होने के बाद पीवी नरसिंह राव ने भी भाजपा शासित कई राज्य सरकारों को गिरा दिया था। वस्तुतः ऐसा अवसर

आ गया कि देश में कहीं न कहीं चुनाव की डुगडुगी बजती रहती है। देश का लगभग 97 करोड़ मतदाता किसी न किसी चुनाव की उलझन में जकड़ा रहता है।

चूंकि संविधान में लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने का उल्लेख तो है, लेकिन दोनों चुनाव एक साथ कराने का हवाला नहीं है। संविधान में इन चुनावों का निश्चित जीवनकाल भी नहीं है। वैसे यह कार्यकाल पांच वर्ष के लिए होता है, लेकिन बीच में सरकार के अल्पमत में आ जाने के कारण या किसी अन्य कारण के चलते सरकार गिर या गिराई जा सकती है। केंद्रीय विधि आयोग ने 2018 में केंद्र सरकार को प्रस्ताव दिया था कि पांच साल के भीतर यदि सरकार के भंग होने की स्थिति बने तो 'रचनात्मक अविश्वास' मत हासिल किया जाए। मसलन, किसी सरकार को लोकसभा या विधानसभा के सदस्य अविश्वास मत से गिरा सकते हैं, तो इसके विकल्प में जिस दल या गठबंधन पर विश्वास हो या जिसे विश्वास मत हासिल हो जाए, उसे बतौर नई सरकार की शपथ दिला दी जाए। कुछ विपक्षी दल एक साथ चुनाव के पक्ष में शायद इसलिये नहीं हैं, क्योंकि उन्हें आशंका है कि ऐसा होने पर जिस दल ने अपने पक्ष में माहिल बना लिया तो केंद्र व ज्यादातर राज्य सरकारें उसी दल की होंगी? जैसे कि सत्रहवीं (2019) लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रवाद की हवा के चलते भाजपा नेतृत्व वाले राजग को बड़ा जनदेष्टे मिला था। ऐसे में यदि विधानसभाओं के भी चुनाव हुए होते तो कांग्रेस समेत क्षेत्रीय दलों का भी सुझाव साफ हो गया होता? हालांकि ऐसा हुआ नहीं था।

बार-बार चुनाव की स्थितियां निर्मित होने के कारण सत्ताधारी राजनीतिक दल को यह भय बना रहता है कि उसका कोई नीतिगत फैसला ऐसा न हो जाए कि दल के समर्थक मतदाता नाराज हो जाएं। लिहाजा सरकारों को लोक-लुभावन फैसले लेने पड़ते हैं। वर्तमान में अमेरिका सहित अनेक ऐसे देश हैं, जहां एक साथ चुनाव बिना किसी बाधा के संपन्न होते हैं। गोया, भारत में भी यदि एक साथ चुनाव की प्रक्रिया 2029 से होती है तो केंद्र व राज्य सरकारों बिना किसी दबाव के देश व लोकहित में फैसले ले सकेंगी। सरकारों को पूरे पांच साल विकास व सुशासन को सुचारू रूप से लागू करने का अवसर मिलेगा।

(जगत फीचर्स)

## संभाग स्तरीय, जिला, विकासखंड एवं नवांकुर संस्थाओं की समीक्षा बैठक संपन्न

-नरेन्द्र दीक्षित

उत्तर प्रदेश, जिला, विकासखंड एवं नवांकुर संस्थाओं की समीक्षा बैठक का आयोजन स्थानीय सांवरिया ढाणी परिसर नर्मदापुरम में आयोजित किया गया। जिसमें मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर, मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं विधायक डॉ. सीतासरन शर्मा, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के कार्यपालक निदेशक डॉ. धीरेंद्र पाण्डे, उपनिदेशक डॉ. वीरेंद्र व्यास विशेष रूप से उपस्थित हुए। इस अवसर पर समीक्षा बैठक में मोहन नागर ने संभाग के तीनों जिला समन्वयक एवं विकासखंड समन्वयकों से विस्तार से चर्चा करते हुए प्रत्येक बिंदु पर समीक्षात्मक आवश्यक जानकारी प्रदान की और डॉ. धीरेंद्र पांडे द्वारा भी विस्तार से सभी लोगों से बात करते हुए आवश्यक

सुझाव दिए। इसके उपरांत नवांकुर समितियों की समीक्षा बैठक में मोहन नागर ने प्रत्येक जिले की दो-दो नवांकुर संस्थाओं के प्रतिनिधियों से उनका प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण के उपरांत समीक्षात्मक आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए ग्राम विकास के विभिन्न आयामों से सभी को परिचित कराया और आदर्श ग्राम की परिकल्पना एवं जंग गंगा संवर्धन अभियान नशा मुक्त भारत अभियान शिक्षा के लिए ऐसे अनेक बिंदुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। डा सीतासरन शर्मा ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि कैसे जन अभियान परिषद ग्राम विकास प्रस्फुटन समितियां नवांकुर समितियां और मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के द्वारा शासन और समाज के बीच में सेतु का कार्य कर रहा है। इस दिशा में भी डॉ सीतासरन शर्मा ने विस्तार से अपने विचार व्यक्त किया और कहा कि भविष्य में भी

किसी प्रकार की आपको आवश्यकता रहेगी तो मैं हर समय आपके लिए उपलब्ध हूँ। डॉक्टर धीरेंद्र पांडे द्वारा भी सभी नवांकुर समितियों को आवश्यक दिशा निर्देश देकर उनके सेक्टर में जो ग्राम पंचायत है वह ग्राम आ रहे हैं उनको सही दिशा में कार्य करने की आवश्यकता के तहत कोऑर्डिनेशन करके ब्लॉक समन्वयक और जिला समन्वयक के माध्यम से कार्य करने के सुझाव दिए। जिला समन्वयक नर्मदापुरम पवन सहलग एवं हरदा जिले के जिला समन्वयक संदीप गौहर द्वारा किये गये कार्यों के विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। संभाग समन्वयक कौशलेश तिवारी ने संभाग स्तरीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर तीनों जिलों के जिला समन्वयक और विकासखंड समन्वयक तथा नवांकुर समितियों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए।

(जगत फीचर्स)

## शिवर की ओर साय सरकार

(पेज 1 का शेष)

दूरदर्शन के आदिवासी इलाकों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास भी जारी हैं। भारत के सबसे कम साक्षर जिलों में से एक बीजापुर में माओवादियों द्वारा बंद किए गए 28 स्कूलों को फिर से खोल दिया गया है। इसके अलावा, शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए स्थानीय बोलियों में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। 18 स्थानीय भाषाओं और बोलियों में पाठ्यपुस्तकें तैयार की जा रही हैं।

### सड़कों और स्कूलों जैसी बुनियादी सुविधाओं

बस्तर संभाग में सुरक्षा उपायों को काफी मजबूत किया गया है। अब हर नौ नागरिकों पर एक अर्धसैनिक बल का जवान है। सड़कों और स्कूलों जैसी बुनियादी सुविधाओं को और बढ़ाने के लिए 250 से अधिक सुरक्षा शिविर और 58 नए शिविर स्थापित करने की योजना पर काम चल रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने वनवासियों की अवस्था को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए हैं। तेंदू पत्ता संग्रहण की दर 4000 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये प्रति मानक बोरा कर दी गई है, जिससे 12 लाख से अधिक संग्रहकों को लाभ मिलेगा। आगामी चरण पादुका योजना से तेंदू पत्ता संग्रहकों को अतिरिक्त सहायता और बोनस मिलेगा।

### आर्थिक विकास को और बढ़ावा

आर्थिक विकास को और बढ़ावा देने के लिए माओवाद प्रभावित जिलों के छात्रों को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। अन्य जिलों के छात्रों को एक प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण मिलेगा, जिससे उन्हें स्वरोजगार की ओर बढ़ने और अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने में मदद मिलेगी। सरकार आदिवासी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के लिए भी प्रतिबद्ध है। स्थानीय विरासत को बढ़ावा देने के लिए बस्तर के पेंताहासिक मेलों को सरकारी संरक्षण और वित्तीय सहायता मिल रही है। छत्तीसगढ़ सरकार के ये व्यापक प्रयास न केवल सुरक्षा को बढ़ा रहे हैं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में विकास को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इन पहलों का उद्देश्य बेहतर शिक्षा, बुनियादी ढांचा, रोजगार के अवसर और सांस्कृतिक संरक्षण प्रदान करके आदिवासी समुदायों के लिए एक उज्वल भविष्य बनाना है।

### विकसित भारत की संकल्पना

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह खुरशी की बात है कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत की संकल्पना को अपने आयोग की थीम बनाया है। युवा उत्सव के दौरान अलग-अलग विषयों को लेकर पैनाल डिस्कशन होंगे, जिसमें युवाओं के लिए उद्यम में अवसर पर बात होगी। सीआईआई और यंग इंडियंस की इस पहल से वर्तमान और भावी पीढ़ी को सफल उद्यमी बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत पर जमाने की प्रौद्योगिकी और रोजगार जरूरतों के मुताबिक स्किल डेवलपमेंट करने और शिक्षा देने की बात पर जोर दे रहा है। इसी कड़ी में हम प्रदेश के आदिवासीबहुल क्षेत्र के युवाओं को अब रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे तकनीकी विषय पढ़ा रहे हैं। प्रदेश के स्कूलों में स्किल डेवलपमेंट का कोर्स शामिल करने से पढ़ाई के साथ ही बच्चे हुनरमंद भी हो रहे हैं।

### आईटी हब के रूप में विकसित कर रहे हैं

साय ने कहा कि हमारे साथ उद्योग जगत के लोग बैठे हैं। आप साय जानते हैं कि प्रदेश में प्रशिक्षित कुशल इंजीनियरों की बहुत अधिक मांग है। इस मांग को पूरी करने हम छत्तीसगढ़ में नए प्रौद्योगिकी संस्थान आरंभ करने जा रहे हैं। इस बजट में हमने आईआईटी की तर्ज पर पांच सीआईटी आरंभ करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके पैदा कर रही है। जल्द ही स्वास्थ्य विभाग में 650 पदों पर मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। एक हफ्ते पहले हमने पुलिस में विभिन्न पदों में भर्तियों के लिए स्वीकृति दी है। नालंदा की तर्ज पर हम सभी नगरीय निकायों में हाइटेक लाइटवैय बनवा रहे हैं। नवा रायपुर को हम आईटी हब के रूप में विकसित कर रहे हैं।

### सिंगल विण्डो सिस्टम 2.0 लागू किया

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमने सिंगल विण्डो सिस्टम 2.0 लागू किया है और नई उद्योग नीति भी ला रहे हैं। छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से हम युवा उद्यमियों को बढ़ावा देंगे। इसके लिए प्रदेश के युवाओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी के साथ ब्याजमुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा प्रदेश मूलतः कृषि आधारित होने से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में विकास की बड़ी संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ फूड प्रोसेसिंग का वैश्विक केंद्र बनेगा। हजारों लोगों को सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि इन उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ा जा सके।

# पर्यावरण है अमूल्य संपदा



आज की बात  
पृथ्वी कणकड़  
स्वतंत्र लेखक

**जगत प्रवाह. गोपाल।** पर्यावरण यात्रिण ऐसा आवरण जो हमें चारों तरफ से ढंक कर रखता है, जो हमसे जुड़ा है और हम उससे जुड़े हैं और हम चाहें तो भी खुद को इससे अलग नहीं कर सकते हैं। प्रकृति और पर्यावरण एक दूसरे का अभिन्न हिस्सा हैं। कोई भी व्यक्ति या वस्तु चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, पर्यावरण के अन्तर्गत ही आती है। पर्यावरण से हमें बहुत कुछ मिलता है, लेकिन बदले में हम क्या करते हैं? हम अपनी स्वायत्त सिद्धि के लिए इस पर्यावरण और इसकी अमूल्य संपदा का हनन करने पर तुले हैं। हमारे द्वारा कि गई हर अच्छी और बुरी गतिविधि का असर पर्यावरण पर पड़ता है। इस प्रकृति पर मानव ही सबसे अधिक बुद्धिशील प्रणी माना जाता है। अतः पर्यावरण के संरक्षण की जिम्मेदारी भी मनुष्य की ही है। आज हम पर्यावरण संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालकर समाज को इसके लिए जागृत करना चाहते हैं।

पर्यावरण अर्थात् जिस वातावरण में हम रहते हैं। हमारे आस पास मौजूद हर एक चीज, जीव-जंतु, पक्षी, पेड़-पौधे, व्यक्ति इत्यादि सभी से मिलकर पर्यावरण की रचना होती है। हमारा इस पर्यावरण से घनिष्ठ संबंध है और हमेशा रहेगा। प्रकृति और पर्यावरण की अद्भुत सुंदरता देखते ही हृदय में खुरशी और उत्साह का संचार होने लगता है। हरे भरे लाहलहाते पेड़, आसमान में कलरव करते और चहचहाते पक्षी, जंगल में दौड़ते जीव जंतु, समन्दर में आती और जाती हुई लहरें, कल कल करके बहती हुई नदियाँ आदि जो मनोमग्न अहसास करवाते हैं, वो हमें अन्य कहीं से महसूस नहीं हो सकता। फिर भी ये अफसोस की बात है कि लोग आज भी

इसके महत्व को समझ नहीं पाए हैं और इसे नुकसान पहुंचाते रहते हैं। वे यह नहीं जान पा रहे कि पर्यावरण की हानि करके वे अपने सर्वनाश को निमंत्रण दे रहे हैं।

जैसे-जैसे समय बीतता गया हमारी जरूरतें भी बढ़ती गईं और इन जरूरतों को पूरा करने

के लिए हम पर्यावरण के प्रति निर्दयता दिखाते लगे। हमने जनसंख्या वृद्धि पर पहले से रोक नहीं लगाई, जिससे लोगों को संसाधन कम पड़ने लगे और अत्यधिक रूप से पर्यावरण का विनाश होने लगा। गाँवों से लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे, पेड़ पौधों और वनों का विनाश होने लगा, जीव जंतुओं को अपने फायदे के लिए मारा जाने लगा, हर तरफ प्रदूषण फैल गया। जिससे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा।

मध्यप्रदेश में भी पिछले कुछ वर्षों में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की दिशा में निरंतर कार्य हुए हैं। सिर्फ सरकार स्तर पर ही नहीं बल्कि सरकार के मंत्री और प्रभावशील लोगों ने भी अपने घरों, शासकीय बंगलों के बाहर लगे पेड़ों को कटवाकर वहां रेत और कंक्रीट का निर्माण करवा लिया गया। यह स्थिति तब है जब प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद रोजाना एक प्रेत कहे जाते हैं और लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने कैबिनेट मंत्री सहित अन्य प्रभावशील लोगों ने पेड़ों को क्षति पहुंचाने का काम किया है। अगर यह काम यही नहीं रुका तो आने वाले समय में पर्यावरण को इसी तरह से नुकसान होगा। (जगत फीचर्स)

## कर्ज के दलदल में धंसी मोहन यादव सरकार

(पेज 1 का शेष)

### चालू वित्त वर्ष में सरकार का तीसरा लोन

छह अगस्त को लिए गए पांच हजार करोड़ कर्ज का 11 और 21 साल की अवधि में ब्याज का भुगतान करना तय किया है। इस कर्ज की राशि अलग-अलग 2500-2500 करोड़ रुपए रही है। कर्ज लेने के बाद सरकार ने 1.29 करोड़ लाइली बहनों को राखी के लिए 250 रुपए और 1250 रुपए की मासिक किश्त, कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के बकाया एरियर्स की राशि का भुगतान किया था। चालू वित्त वर्ष में मोहन सरकार यह तीसरा कर्ज ले रही है।

### विरासत में मिला मोहन सरकार को 3.5 लाख करोड़ का कर्ज

पिछले साल नवंबर में विधानसभा चुनाव के बाद बनी मोहन यादव सरकार को 3.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज विरासत में मिला था। मगर सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में 42,500 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था, जिसमें से मोहन यादव सरकार ने 1 जनवरी 2024 से 31 मार्च के बीच सिर्फ तीन महीनों में ही 17,500 करोड़ रुपए लगभग 41 फीसदी कर्ज लिया था। मध्य प्रदेश सरकार को मुफ्त वाली योजनाएँ भारी पड़ रही हैं। आर्थिक मामलों के जानकार कहते हैं कि 'कर्ज लेकर धी पीने की प्रवृत्ति' घातक साबित हो सकती है। मध्य प्रदेश में भले खुद सरकार यह 'धी' नहीं पी रही हो, लेकिन यह मुफ्त की रेखाड़ी बाँकर लोगों को 'धी' पिला रही है। यही कारण है कि अब प्रदेश सरकार कर्ज की सीमा में गले तक डूब चुकी है। यह बात भी सही है कि प्रदेश में जारी बड़ी विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कर्ज का सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है।

### किसी चुनौती से कम नहीं राशि का इंतजाम

बोते एक दरमक में सरकार ने प्रदेश के मतदाताओं के लिए बिजली पर अनुदान, कृषि के लिए अनुदान, विद्यार्थियों के लिए लेनपट्टा और स्कूटी, लाइली बहना योजना जैसी दर्जनों योजनाएँ संचालित कीं। प्रदेश की जनता इससे लाभान्वित तो हो रही है, लेकिन इसके लिए भारी-भरकम राशि का इंतजाम करना किसी चुनौती से कम नहीं है। कर्ज लेकर किसी तरह इन योजनाओं को संचालित किया जा रहा है, लेकिन अब

इन योजनाओं के लिए राशि का इंतजाम करना सरकार को भारी पड़ने लगा है। अपने वादों को पूरा करने के लिए व्यय और आय के बढ़ते अंतर को कम करना बेहद आवश्यक है। इसके लिए सरकार को आय के नए साधन खोजना होंगे। मुश्किल यहाँ भी यही होगी कि सरकार को आय बढ़ोतरी के लिए विविध टैक्स बढ़ाने के विकल्प से बचना होगा।

### बाक्स सरकार ने कब, कितना लिया कर्ज

महीना	कर्ज का राशि
05 जनवरी 2023	2000 करोड़
02 फरवरी 2023	3000 करोड़
09 फरवरी 2023	3000 करोड़
16 फरवरी 2023	3000 करोड़
23 फरवरी 2023	3000 करोड़
02 मार्च 2023	3000 करोड़
09 मार्च 2023	2000 करोड़
17 मार्च 2023	4000 करोड़
24 मार्च 2023	1000 करोड़
29 मई 2023	2000 करोड़
14 जून 2023	4000 करोड़
12 सितंबर 2023	1000 करोड़
27 दिसंबर 2023	2000 करोड़
23 जनवरी 2024	2500 करोड़
7 फरवरी 2024	3000 करोड़
22 मार्च 2024	5000 करोड़
6 अगस्त 2024	5000 करोड़

### पांच माह में 17500 करोड़ का कर्ज लिया

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के प्रावधान के अनुसार, सरकार राज्य सफल धरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत तक ऋण ले सकती है। सरकार नियमों के अनुसार ही कर्ज लेने जा रही है। वर्ष 2024-25 में सरकार 65 हजार करोड़ तक कर्ज ले सकती है।

### पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री को धेरा

भाजपा शासन के समय सबसे ज्यादा कर्ज लेने की बात से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ खासे नाराज हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार कर्ज के दलदल में भंसेती जा रही है। यह कर्ज दो बार में ढाई-ढाई हजार करोड़ रुपए के रूप में लिया जाएगा। कर्जखोरी को लेकर कमलनाथ ने राज्य सरकार को निशाने पर लिया है। कमलनाथ ने कहा कि 'मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार कर्ज

लो और धी पियो के सिद्धांत पर चल रही है। सरकार एक बार फिर से पाँच हजार करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। प्रदेश पर पहले से ही 3.8 लाख करोड़ का कर्ज है। कमलनाथ ने कहा 'प्रदेश को कर्ज के दलदल में डुबाने वाली भाजपा सरकार के मुँह से आज तक यह नहीं सुना कि अगर प्रदेश के ऊपर कर्ज बढ़ रहा है तो सरकार फिजूल खर्च में कमी करने के लिए कोई कदम उठाने जा रही है। लगातार कर्ज लेने के बावजूद न तो प्रदेश में निवेश बढ़ा है, न रोजगार बढ़ा है, न नौकरी बढ़ी है, न ही गैंगू और धान का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है और न ही लाइली बहनों को तीन हजार रुपये प्रति महीने दिए जा रहे हैं।

### कैंग भी जता चुका है राजकोषीय घाटे पर चिंता

हाल ही में कैंग ने अपनी रिपोर्ट में सरकार के बढ़ते राजकोषीय घाटे पर चिंता जताते हुए कहा था कि सरकार को ज्यादा कर्ज लेने के बजाय राजस्व बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए।

### पिछले साल की तुलना में 38 फीसदी अधिक कर्ज

पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 के मुकाबले यह कर्ज 38 प्रतिशत ज्यादा है। गौरतलब है कि साल 2023-24 में मध्य प्रदेश सरकार ने 55 हजार 708 रुपए का कर्ज लिया था। हालांकि सरकार निश्चित है, ज्यादा कर्ज लेने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा कहते हैं कि सबकुछ नियम के अनुसार ही लिया जा रहा है। उनका कहना है कि सरकार विकास के लिए कर्ज लेती भी है और समय पर उनका भुगतान भी करती है।

### साल 2003 तक राज्य पर 20,000 करोड़ रुपये का कर्ज था

जब साल 2003 तक प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार थी, उस समय राज्य पर 20,000 करोड़ रुपये का कर्ज था। मध्यप्रदेश के प्रति व्यक्ति पर लगभग 3,300 रुपये का कर्ज उस समय था। लेकिन यह कर्ज समय के साथ-साथ दिन दोगुना और रात चौगुना बढ़ता चला गया। वर्तमान में सरकार पर लगभग लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है। सरकार लगभग 20,000 करोड़ रुपये ब्याज चुका रही है। इसके बाद भी मध्यप्रदेश में घोषणाओं का सिलसिला जारी है। इसी के चलते सरकार को कई बार हजारों करोड़ का कर्ज भी लेना पड़ा है।



विष्णु के सुशासन से  
सँवर रहा छत्तीसगढ़



श्री नरेन्द्र मोदी  
माननीय प्रधानमंत्री



श्री विष्णु देव साय  
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

# सुशासन से विकास की नई राह...

- ❖ कृषक उन्नति योजना : धान का प्रति विघंटल 3100 रुपए मिल रहा दाम, खेती-किसानी से खुले समृद्धि के द्वार
- ❖ मुख्यमंत्री आवास योजना (वागीण) : 47 हजार 90 आवासहीन वागीण परिवारों को मिलेगा लाभ

- ❖ शासकीय भर्ती में आयु सीमा में छूट: पुलिस विभाग सहित शासकीय भर्तियों में युवाओं को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट
- ❖ अष्टाचार मुक्त पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित



- ❖ मुफ्त अनाज: छत्तीसगढ़ के 68 लाख गरीब परिवारों को अगले पांच साल तक नि:शुल्क राशन
- ❖ तैदूपत्ता संग्राहक पारिश्रमिक: 4000 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये प्रति मानक बोरा

- ❖ 'नियत नेल्लानार' अभियान के साथ नक्सल समस्या के पूर्ण निदान के प्रभावी कदम
- ❖ त्वरित निर्णय, सख्त प्रशासन: विष्णु देव सरकार में अब तक 150 नाजीवादी मुठभेड़ में डेर, 599 की गिरफ्तारी, 510 में किया आत्मसमर्पण

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से जुड़ने के लिए यह क्यूआर कोड स्कैन करें...

हमने बनाया है, हम ही सँवारेगे



Visit us : [f ChhattisgarhCMO](#) [X ChhattisgarhCMO](#) [C ChhattisgarhCMO](#) [ChhattisgarhCMO](#) [f DPRChhattisgarh](#) [X DPRChhattisgarh](#) [www.dprcg.gov.in](#)

स्वामीजी महाराज